

[2016] 8 एस.सी.आर. 803

सरकारी. बिहार और अन्य के. वगैरह। वगैरह

बनाम

दयानंद सिंह आदि। वगैरह।

(2016 की सिविल अपील संख्या 9921-9923)

29 सितंबर 2016

[जे, चेलमेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

न्यायिक सेवा: आरक्षण - अपीलकर्ता द्वारा सेवा नियमों में संशोधन - राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के पक्ष में न्यायिक सेवाओं में पदों का आरक्षण प्रदान करती है - उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश द्वारा, आक्षेपित नियमों को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि संशोधन नहीं थे जैसा कि कला के अंतर्गत विचार किया गया है, उच्च न्यायालय के साथ उचित परामर्श से पहले। 233 और 234 -अपील पर, आयोजित: संशोधनों से पहले जो परामर्श हुआ वह निश्चित रूप से संदर्भ में आवश्यक परामर्श के अपेक्षित मानकों से कम रहा -आक्षेपित नियमों को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया गया -अपीलकर्ता में न्यायिक सेवाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं -हालाँकि, मौजूदा मुकदमे के लंबित होने के मद्देनजर, भर्ती प्रक्रिया के संबंध में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया, जो बीच में शुरू हुई थी लेकिन रोक दी गई थी, शीघ्रता से शुरू की जाए -बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951 -आर.4ए -बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1965 -आर.3ए -भारत का संविधान कला। 233 और 234.

आरक्षण -न्यायिक सेवा में -न्यायपालिका की तुलना में कार्यपालिका की भूमिका/शक्ति - संवैधानिक अनिवार्यताओं और सीमाओं पर चर्चा की गई -धारणा: संविधान की योजना के तहत, कार्यपालिका आरक्षण के लिए नीति तैयार करने वाली एकमात्र प्राधिकारी नहीं है -यह एक के तहत है ऐसी नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करना संवैधानिक दायित्व है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

माना गया: 1. 2009 में, बिहार राज्य ने अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया, जिन्हें (i) बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951, (ii) बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1965 के रूप में जाना जाता है। नागरिकों के विभिन्न पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए क्रमशः नियम 4ए और नियम 3ए पेश करके। [पैरा 6]

2.1 उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य की उन दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जिनके द्वारा विवादित नियम बनाए गए थे। निर्णय मुख्य रूप से इस निष्कर्ष पर आधारित था कि संशोधनों से पहले अनुच्छेद 233 और 234 के तहत उच्च न्यायालय के साथ उचित परामर्श नहीं किया गया था। [पैरा 7]

2.2 उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि संशोधनों से पहले जो परामर्श हुआ वह निश्चित रूप से संदर्भ में आवश्यक परामर्श के अपेक्षित मानकों से कम था और दोनों विवादित नियमों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता है। [पैरा 10]

3.1 बिहार सरकार के रुख से यह स्पष्ट है कि नीतिगत रूप से बिहार राज्य की न्यायिक सेवाओं में भी नागरिकों के विभिन्न पिछड़े वर्गों के पक्ष में उचित आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। हालाँकि, संविधान की योजना के तहत, कार्यपालिका ऐसी नीति बनाने या उसे लागू करने का एकमात्र प्राधिकारी नहीं है। न्यायिक सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने की ऐसी नीति को तैयार करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करना कार्यपालिका का संवैधानिक दायित्व है। [पैरा 15]

बिहार राज्य और अन्य बनाम बाल मुकुंद साह और अन्य (2000) 4 एससीसी 640: 2000 (2) एससीआर 299 -पर भरोसा किया गया।

3.2 आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के अस्तित्व का आकलन अनिवार्य रूप से विधायिका या कार्यपालिका का कार्य है, जैसा भी मामला हो, और नीति चयन के दायरे में है। लेकिन नीति तैयार करने की शक्ति कुछ संवैधानिक अनिवार्यताओं और सीमाओं द्वारा संरचित है, जैसे। (i) राज्य में पिछड़े वर्गों के अस्तित्व की पहचान करना, (ii) यह राय बनाना कि राज्य की न्यायिक सेवाओं में ऐसे वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है (iii)

इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या होगा न्यायिक सेवाओं की दक्षता बनाए रखने के दायित्व के अनुरूप न्यायिक सेवा के संदर्भ में आरक्षण का उचित प्रतिशत आवश्यक है। इस तरह के आकलन राज्य की कार्यकारी और न्यायिक दोनों शाखाओं के संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत विचारों पर किए जाने की आवश्यकता है। यह माना जाता है कि बिहार राज्य, बिहार राज्य की न्यायिक सेवा में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में अपने स्वयं के मूल्यांकन पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करके सी01,1सल्टेशन की प्रक्रिया शुरू करने का हकदार है। राज्य को राज्य की न्यायिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और न्यायिक सेवाओं में आरक्षण के वांछनीय प्रतिशत और प्रासंगिक सामग्री जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, के संबंध में अपना मूल्यांकन भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद उच्च न्यायालय को राज्य द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए, राज्य द्वारा किए गए प्रस्ताव की सत्यता का उचित मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी राय और ऐसी राय के कारणों से राज्य को अवगत कराना चाहिए। यदि राज्य और उच्च न्यायालय के बीच आम सहमति होती है, तो राज्य आरक्षण प्रदान करने वाले उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। किसी भी मतभेद की स्थिति में, सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा सूचित निष्कर्षों को स्वीकार करने में असमर्थता के कारणों को दर्ज करना चाहिए और ऐसी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले विभिन्न संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार नियमों में संशोधन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। (पैरा 16, 17)

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और क्यूथर्स बनाम भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: 1993 (2) सप्ल। एससीआर 659-संदर्भित।

3.3 न्यायिक सेवाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियों की मौजूदगी को देखते हुए, पूरी प्रक्रिया शीघ्रता से अधिमानतः 1 जनवरी, 2017 तक पूरी की जानी चाहिए। इसके बाद, न्यायिक सेवा में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी संबंधित पक्षों द्वारा शीघ्रता से पूरा किया जाएगा और 30 जून, 2017 तक पूरा किया जाएगा। [पैरा 18]

इंद्र स्मव्हनी बनाम भारत संघ और अन्य (2000) 1 एससीसी 168: 1999 (5) पूरक। एससीआर 229 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1999 (5) पूरक। एससीआर 229	पैरा 5	को संदर्भित करता है
2000 (2) एससीआर 299	पैरा 15 और 16	निर्भर करता है
1993 (2) सप्ल एससीआर 659	पैरा 17	को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 9921 9923।

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 14677/2009, I 0226/2010 और 7508/2011 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.11.2014 से।

साथ

2016 का सी. ए. नंबर 9924।

एसएलपी (सी) संख्या 11363-11364, 14625-14626, 2015 का 22190

पी.एस. पटवालिया, एसजी, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, समीर अली खान, मौर्य विजय चंद्र, श्रीयान सिन्हा, शशांक सिंह, प्रेम प्रकाश, शशांक क्र. सौरव, डी.के. देवेश, गौतम सिंह, साकेत सिंह, एस.के. रोशन, रितेश खत्री, नितिन क्र. ठाकुर, विज्ञापन बनाम अपीलकर्ताओं के लिए।

अमरेंद्र शरण, प्रवीण एच. पारेख, गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, क्षत्रशाल राज, विशाल प्रसाद, सुश्री अपराजिता मुखर्जी, मिस. पारेख एंड कंपनी, नवीन प्रकाश, संजय कुमार दुबे, राकेश कुमार तिवारी, सुश्री शुचि सिंह, देवेन्द्र क्र. शुक्ला, अनिल के. मिश्रा, चक्रपाणि, अनुराग सिंह, यादव नरेन्द्र सिंह, कृष्ण कांत दुबे, उपेन्द्र एन. मिश्रा, सत्येन्द्र श्रीवास्तव, विवेक वर्धन, राज चतुर्थ नंदन द्विवेदी, चक्रपाणि, अनुराग सिंह, अनिल कुमार मिश्रा, अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए.

राकेश कुमार, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

आदेश

एसएलपी (सी) नंबर I 0163-10165/2015 और एसएलपी (सी) नंबर I 1365/2015

1. छुट्टी स्वीकृत.

:: ये अपीलें उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिकाओं के एक समूह में पारित दिनांक 10.11.2014 के एक सामान्य निर्णय से व्यथित हैं। एसएलपी (सी) संख्या 10163 10165/2015 से उत्पन्न सिविल अपीलें बिहार राज्य द्वारा दायर की जाती हैं। एसएलपी (सी) संख्या 11365/2015 आदि से उत्पन्न होने वाली अन्य सिविल अपीलें उपर्युक्त याचिकाओं के विभिन्न पक्षों, यानी याचिकाकर्ताओं और अन्य उत्तरदाताओं द्वारा दायर की जाती हैं।

3. इन अपीलों में विवाद संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत एससी/एसटी/ओबीसी जैसे नागरिकों के विभिन्न पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के बिहार राज्य के अधिकार के संबंध में है। आदि बिहार राज्य की उच्च और अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं (इसके बाद सामूहिक रूप से न्यायिक सेवाओं के रूप में संदर्भित) में।

4. हमें सूचित किया गया है कि 1991 से पहले न्यायिक सेवाओं पर लागू प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत, कुछ पद केवल एससी और एसटी श्रेणियों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षित थे, जिनका विवरण इस समय आवश्यक नहीं हो सकता है। वर्ष 1991 में, बिहार राज्य ने पदों और सेवाओं (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) में रिक्तियों का बिहार आरक्षण अधिनियम, 1991 नामक एक अधिनियम बनाया। उक्त अधिनियम में विभिन्न पदों के पक्ष में कुछ प्रतिशत पदों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में नागरिकों के निर्दिष्ट वर्ग। सवाल उठा कि क्या उक्त अधिनियम लागू होगा और उसमें दिए गए आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवाओं तक बढ़ाया जाएगा। आखिरकार, इस न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य और ए11अन्य बनाम बाल मुकुंद साह और अन्य**, (2000) 4 एससीसी 640 में इस प्रश्न की जांच की गई। इस न्यायालय ने, अधिनियम के शाब्दिक निर्माण पर, राय दी कि अधिनियम का अनुप्रयोग यहां तक कि विस्तारित है न्यायिक सेवाओं के लिए.

"27. ... परिभाषा प्रावधानों के साथ पढ़े गए धारा 4 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्यक्त भाषा पर तर्क की इस पंक्ति की सराहना करना मुश्किल है। यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी कार्यालय का शब्द बिहार राज्य की न्यायपालिका में स्वाभाविक रूप से न केवल मंत्रालयिक कर्मचारी शामिल होंगे, बल्कि राज्य की न्यायपालिका में शामिल अदालतों के पीठासीन अधिकारियों सहित अधिकारी भी शामिल होंगे। एक बार जब अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की स्पष्ट भाषा

पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है यह माना गया कि धारा 4 का जोर जिला न्यायालयों के साथ-साथ उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण को नियंत्रित करने के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सभी बिहार राज्य की न्यायपालिका का हिस्सा होंगे और राज्य न्यायपालिका में कार्यालयों के धारकों के रूप में माना जाना होगा।

" हालाँकि, इस न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम का ऐसा निर्माण अधिनियम को असंवैधानिक बना देगा। इस तरह के निष्कर्ष का कारण यह है कि न्यायिक सेवाओं से संबंधित भारत के संविधान की योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य विधानमंडल न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी कानून बनाने में अक्षम होगा। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति केवल अनुच्छेद 233 और 234 में निहित नुस्खे के अनुसार की जानी है।

"36. इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि जिला न्यायाधीश के पद पर कोई भी भर्ती उच्च न्यायालय की सिफारिश के बिना राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार, जमीनी स्तर पर अधीनस्थ न्यायपालिका में भी नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती हैं उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनके द्वारा बनाए गए नियमों को छोड़कर। कोई भी वैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालय के परामर्श को दरकिनार कर और एक वैधानिक आदेश निर्धारित करके जैसा कि धारा 4 के अधिनियमन द्वारा करने की कोशिश की जाती है। बिहार विधानमंडल को जिला न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों पर भर्ती और नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा अनुमति और परिकल्पना के अनुसार पूर्ण संहिता के साथ सीधे टकराव में माना जाता है। इसलिए, धारा 4 पर आपत्ति जताई गई है। जहां तक जिला न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती के विषय का संबंध है, राज्य विधानमंडल के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित और निषिद्ध क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। उस क्षेत्र को अनुच्छेद 309 के सामान्य स्वीप के संचालन से अलग कर दिया गया है।"

5. इस न्यायालय ने आगे कहा कि यह बिहार के राज्यपाल के लिए खुला है कि वह कानून के अनुसार और उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक सेवाओं में व्यक्तियों के आरक्षण के लिए उचित नियम बनाएं।

"37 यह केवल राज्यपाल है जिसे उक्त कार्य सौंपा गया है जिसे उसे उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद और न्यायपालिका में भर्ती के लिए उचित नियम बनाकर करना है। अनुच्छेद 234 द्वारा दिए गए जमीनी स्तर पर और अनुच्छेद 233 उप-अनुच्छेद (2) द्वारा निर्धारित जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए बार से सीधी भर्ती के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश पर ही कार्य किया जा सकता है।

" यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आरक्षण के लिए ऐसा प्रावधान करते समय राज्यपाल ऐसी शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने वाले कानून के विभिन्न सिद्धांतों से बंधे होते हैं। प्रासंगिक सिद्धांत इंद्रा सॉ/मे केस¹ आदि में प्रतिपादित किए गए हैं।

6. 2S1 जून, 2009 को, बिहार राज्य ने अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया, जिन्हें (i) बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951, (ii) बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1965 के रूप में जाना जाता है। नागरिकों के विभिन्न पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए क्रमशः नियम 4ए और नियम 3ए पेश करके। नए शुरू किए गए दोनों नियम काफी हद तक समान हैं²

7. उपर्युक्त दो नियमों को रिट याचिकाओं के एक बैच में चुनौती दी गई जिसमें अपील के तहत निर्णय दिया गया। अपील के तहत निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य की उन दो अधिसूचनाओं³ को रद्द कर दिया जिनके द्वारा आक्षेपित नियम बनाए गए थे। निर्णय मुख्य रूप से इस निष्कर्ष पर आधारित था कि संशोधनों से पहले अनुच्छेद 233 और 234 के तहत उच्च न्यायालय के साथ उचित परामर्श नहीं किया गया था।

"मेरे विचार में, राज्य सरकार द्वारा जिस पत्राचार पर भरोसा किया गया, उसे शायद ही शब्द के वास्तविक अर्थों में परामर्श कहा जा सकता है। पत्र लिखना और न्यायिक सेवाओं में वांछित आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की गंभीरता प्रदर्शित करना, परामर्श नहीं कहा जा सकता है राज्य सरकार को विभिन्न वर्गों के सामान्य प्रतिनिधित्व, न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या और न्याय प्रदान करने के संबंध में उच्च मानकों के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की राय पर ध्यान देना आवश्यक था।

8. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने फैसले में संशोधन के तरीके और ऐसे संशोधनों की वांछनीयता के संबंध में कई अन्य टिप्पणियां कीं। हमारी राय में, न्यायालय के समक्ष मुद्दे के संदर्भ में ऐसी टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह राज्य का विधायी निर्णय था जो उसके समक्ष विवाद का विषय था, जबकि उच्च न्यायालय के पास निस्संदेह 'कानून' की संवैधानिकता, कानून के पीछे के उद्देश्यों को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। और विधायी निकाय का ज्ञान न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।

9. हमने बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और विभिन्न प्रतिस्पर्धी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। हमने राज्य सरकार और प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों के बीच हुए पत्राचार और ऐसे निर्णयों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा की गई सामग्री का भी अध्ययन किया है।

10. हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं कि संशोधनों से पहले जो परामर्श हुआ वह निश्चित रूप से संदर्भ में आवश्यक परामर्श के अपेक्षित मानकों से कम था। हमें उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता कि दोनों विवादित नियमों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता है। हम तदनुसार निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

11. हालाँकि, इस लंबे मुकदमे की प्रक्रिया में 25 साल बीत गए। पहला दौर वर्ष 1991 में रिट याचिकाओं के साथ शुरू हुआ जो अंततः **बाल मुकुंद** मामले में समाप्त हुआ। वर्ष 2009 में न्यायिक सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन के साथ दूसरा दौर। हालाँकि, उक्त तिमाही शताब्दी के दौरान, बिहार राज्य की न्यायिक सेवाओं में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए थे। फ़िलहाल हमारा संबंध केवल वर्ष 2009 और 2012 में उठाए गए कदमों से है।

12. वर्ष 2009 में, बिहार राज्य ने 217 पदों को भरने के लिए और वर्ष 2012 में, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अन्य 118 पदों को भरने के लिए कार्यवाही शुरू की।

13. जहां तक 217 पदों को भरने के लिए वर्ष 2009 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया का सवाल है, हमारे समक्ष यह (सभी तरफ से) सहमति है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और पद भरे हुए हैं। जहां तक 2012 में 118 पदों के लिए भर्ती का सवाल है, हालांकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल 88 सफल उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है (विभिन्न आदेशों के कारण, चाहे उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के अंतरिम या अंतिम)। हमें यह भी सूचित किया गया है कि 92 सफल उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, लेकिन केवल 88 ही वास्तव में शामिल हुए और अन्य 4 सेवा में शामिल नहीं हुए।

14. हमें सूचित किया गया है कि, 13.1.2016 को, बिहार राज्य द्वारा जूनियर सिविल जजों के 206 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगने के लिए एक और विज्ञापन जारी किया गया था। हमें सूचित किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम परीक्षा देने के लिए पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। लेकिन वर्तमान मुकदमे की लंबितता को देखते हुए, प्रक्रिया को रोक दिया गया है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि उपर्युक्त अधिसूचना के बाद, नए पदों के सृजन या अन्यथा कुछ और रिक्तियां उत्पन्न हुईं। कुल मिलाकर, आज की तारीख में जूनियर सिविल जजों के 406 पद खाली पड़े हैं और ऐसे पदों को भरने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दरअसल, न्यायिक सेवा में बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

15. हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों से, बिहार सरकार के रुख से यह स्पष्ट है कि नीतिगत मामले के रूप में न्यायिक सेवाओं में भी नागरिकों के विभिन्न पिछड़े वर्गों के पक्ष में उचित आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। बिहार राज्य. हालाँकि, संविधान की योजना के तहत, कार्यपालिका ऐसी नीति बनाने या उसे लागू करने का एकमात्र प्राधिकारी नहीं है। न्यायिक सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने की ऐसी नीति को तैयार करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करना कार्यपालिका का संवैधानिक दायित्व है। इस संबंध में कानूनी स्थिति इस न्यायालय द्वारा एक से अधिक अवसरों पर स्पष्ट की गई है। बिहार राज्य के संदर्भ में, कानून **बाल मुकुंद मामले** (सुप्रा) में घोषित किया गया है।

16. इस न्यायालय ने **बाल मुकुंद मामले** में कहा कि उच्च न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्था को "आरक्षण की योजना की आवश्यकता" के प्रति अनभिज्ञ नहीं माना जा सकता है।

"32 ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते अनुच्छेद 16(4) के तहत सक्षम प्रावधान का सहारा लेकर उचित मामलों में यदि आवश्यक हो तो आरक्षण की योजना की आवश्यकता से अनजान हो सकते हैं। . "

आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के अस्तित्व का आकलन अनिवार्य रूप से विधायिका या कार्यपालिका का कार्य है, जैसा भी मामला हो, और नीति चयन के दायरे में है। लेकिन नीति बनाने की शक्ति कुछ संवैधानिक अनिवार्यताओं और सीमाओं द्वारा संरचित है। वे हैं (i) राज्य में पिछड़े वर्गों के अस्तित्व की पहचान करना, (ii) यह राय बनाना कि राज्य की न्यायिक सेवाओं में ऐसे वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, (iii) इस प्रश्न का निर्धारण JUDICIAL_SERVICES की दक्षता बनाए रखने के दायित्व के अनुरूप न्यायिक सेवा के संदर्भ में आवश्यक आरक्षण का उचित प्रतिशत क्या होगा। राज्य की कार्यकारी और न्यायिक दोनों शाखाओं के संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत विचारों पर इस तरह के आकलन की आवश्यकता होती है।

17. इसलिए, हम मानते हैं कि बिहार राज्य, बिहार राज्य की न्यायिक सेवा में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में अपने स्वयं के मूल्यांकन पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करके परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने का हकदार है। बिहार राज्य में पिछड़े वर्गों का अस्तित्व और उनकी पहचान विवाद में नहीं है। राज्य को राज्य की न्यायिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और न्यायिक सेवाओं में आरक्षण के वांछनीय प्रतिशत और प्रासंगिक सामग्री जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, के संबंध में अपना मूल्यांकन भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद उच्च न्यायालय को राज्य द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए, राज्य द्वारा किए गए प्रस्ताव की सत्यता का उचित मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी राय और ऐसी राय के कारणों से राज्य को अवगत कराना चाहिए। यदि राज्य और उच्च न्यायालय के बीच आम सहमति होती है, तो राज्य आरक्षण प्रदान करने वाले उचित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। किसी भी मतभेद की स्थिति में, सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा सूचित निष्कर्षों को स्वीकार करने में असमर्थता के कारणों को दर्ज करना चाहिए और ऐसी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले विभिन्न संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार नियमों में संशोधन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने की आवश्यकता है "...यह निर्धारित करने के लिए नहीं कि उनमें से कौन अधिक महत्व का हकदार

हैं या बहस के अंत में विजेता का पुरस्कार लेगा। कार्य (हमारे सामने) इस धारणा के साथ किया जाना है ""।

18. न्यायिक सेवाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियों की मौजूदगी को देखते हुए, यह वांछनीय है कि पूरी प्रक्रिया 1 जनवरी, 2017 तक शीघ्रता से पूरी कर ली जाए। इसके बाद, रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। न्यायिक सेवा को सभी संबंधितों द्वारा शीघ्रता से शुरू किया जाएगा और 30 जून, 2017 तक पूरा किया जाएगा।

19. हम एक नाजुक समस्या से बचे हुए हैं। यदि नियम 3ए (उपर्युक्त रूप से संदर्भित) वैध होता, तो कुछ पिछड़े वर्गों से संबंधित कुछ उम्मीदवार 2012 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्त होने के हकदार होते। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियम को ही अवैध घोषित कर दिया गया है, वे किसी भी आरक्षित कोटा के तहत नियुक्त होने के अधिकार के हकदार नहीं हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि (i) न्यायिक सेवा में बड़ी संख्या में रिक्तियां मौजूद हैं, (ii) डी आरक्षण का प्रश्न एक चौथाई सदी से लंबित है, (iii) राज्य की संभावना की दूरदर्शिता पूरी तरह से स्थापित करने में विफल रही है न्यायिक सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के कारण, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि इन उम्मीदवारों को 2012 की अधिसूचना (118 रिक्तियों को भरने की मांग) के बाद उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध सेवा में नियुक्त किया जाए। उनकी नियुक्ति उन रिक्तियों के विरुद्ध उचित रूप से समायोजित की जाएगी जो अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 (सुप्रा में संदर्भित) के तहत भर्ती का विषय है और उसके बाद उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध उचित रूप से समायोजित की जाएगी। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार नियुक्त किए गए उम्मीदवार सभी उद्देश्यों के लिए 118 उम्मीदवारों (जिनमें से कुछ पहले ही नियुक्त हो चुके हैं और अन्य को नियम 3ए के संदर्भ के बिना नियुक्त किया जाना है) के बाद उनका स्थान लेंगे। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

एसएलपी(सी) संख्या 11363-11364/2015 और एसएलपी(सी) संख्या 14625-14626/2015

20. यह सहमति है कि SLP(C) No.10163-10165 of 2015 से उत्पन्न सिविल अपील में पारित उपरोक्त आदेश के मद्देनजर, इन विशेष अनुमति याचिकाओं में कुछ भी नहीं बचता है। इन याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

एसएलपी(सी)नं.22190/2015

विलंब क्षमा किया गया.

21. याचिकाकर्ता (एक वकील) हमारे सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। अपील के तहत फैसले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई हैं। हमें सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता एक मामले में बी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ दलीलें दीं।

22. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के आचरण के संबंध में टिप्पणियाँ की गई हैं, हम इस मामले की जांच नहीं करना उचित समझते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए यह खुला छोड़ देते हैं कि वह उचित आवेदन के साथ उच्च न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है। टिप्पणियों को मिटा दिया जाए. उच्च न्यायालय ऐसे आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करने के लिए स्वतंत्र है।

23. विशेष अनुमति याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

दिव्या पांडे

मामलों का निपटारा किया गया.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।